बूनो फर्नांडिस बोले- 'बेहद दुखी, निराश और हताश हूं'

Page-04

भारतवर्ष
सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

धमाल 4: उबाऊ चुटकुले और ख़राब वीएफएक्स ने बिगाड़ा खेल

Page-05

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कई विभागों को मिले नए प्रमुख

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करते हुए 20 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर देर रात जारी किए गए आदेशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और विभिन्न विभागों के कार्यों में तेजी लाना बताया जा रहा है। शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, बिजली वितरण, संस्कृति, श्रम और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शुभा वर्मा को नया श्रम आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई जिलों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक अनुभव का बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया गया है। सरकार का मानना है कि बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए समय-समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव आवश्यक होता है हाल के महीनों में प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना, निवेश, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों पर तेजी से काम कर रही है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर किए गए ये बदलाव इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक माने जा रहे हैं। शासन ने उम्मीद जताई है कि नए पदस्थापित अधिकारी अपने-अपने विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाने, योजनाओं की निगरानी मजबूत करने और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभाएंगे।

न्यूज़ीलैंड का भारत को बड़ा तोहफा

पीएम मोदी की यात्रा से पहले 0% टैरिफ का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय न्यूज़ीलैंड दौरे से ठीक पहले वहां की सरकार ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला बड़ा फैसला लिया है। न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लेक्सन ने भारतीय उत्पादों पर कई प्रमुख श्रेणियों में 0% आयात शुल्क (Zero Tariff) लागू करने की घोषणा की है। इस फैसले को दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने और मुक्त व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घोषणा ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही न्यूज़ीलैंड पहुंचने वाले हैं, जिससे इस निर्णय का कूटनीतिक महत्व भी बढ़ गया है।न्यूज़ीलैंड सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करना तथा आर्थिक साझेदारी को दीर्घकालिक आधार प्रदान करना है। शून्य शुल्क नीति लागू होने से भारतीय कृषि उत्पादों, खाद्य सामग्री, औद्योगिक वस्तुओं, वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पादों और अन्य निर्यात क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और न्यूज़ीलैंड के बाजार में भारतीय उत्पाद अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणा भारत-न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों को भी गति दे सकती है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है, लेकिन अब टैरिफ में कमी से निवेश और व्यापारिक गतिविधियों के और विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के उद्योग जगत ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है।प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान व्यापार, कृषि, शिक्षा, तकनीक, रक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में न्यूज़ीलैंड का यह कदम केवल आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि भारत के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी का स्पष्ट संकेत भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर दिखाई देगा।

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला: मुजराई मंदिरों में 24 घंटे CCTV निगरानी

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन को लेकर उठे विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य के मंदिरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने मुजराई विभाग (हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग) के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में दान पेटियों (हुंडी) और चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय का उद्देश्य मंदिरों में प्राप्त दान के संग्रह, सुरक्षा और लेखा-जोखा को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब मंदिरों में रखी दान पेटियों को खोलने से लेकर उसमें मौजूद नकदी निकालने, उसकी गिनती करने और बैंक में जमा कराने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। इसके साथ ही मंदिर परिसरों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम से किया जाएगा, जो सीधे संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय से जुड़ा रहेगा। इससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करने और मंदिरों के वित्तीय प्रबंधन को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

AIMIM को झटका

गोवंडी की पार्षद रोशन शेख की सदस्यता रद्द

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। गोवंडी के वार्ड संख्या 138 से निर्वाचित पार्षद रोशन शेख की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई जाति जांच समिति द्वारा उनके अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किए जाने के बाद की गई।रोशन शेख ने नगर निगम चुनाव ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट से जीता था। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, उसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। विस्तृत परीक्षण के बाद संबंधित समिति ने प्रमाणपत्र को वैध नहीं माना और उसे निरस्त कर दिया। इसके बाद बीएमसी प्रशासन ने कानूनी प्रावधानों के तहत उनकी पार्षद सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए वैध जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है। यदि बाद में प्रमाणपत्र अमान्य पाया जाता है तो निर्वाचन स्वतः निरस्त माना जाता है। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब संबंधित वार्ड में आगे की चुनावी प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और नगर निगम आवश्यक निर्णय लेंगे।इस घटनाक्रम को मुंबई की स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे बीएमसी में AIMIM की स्थिति प्रभावित हो सकती है। विपक्षी दलों ने इस मामले को चुनावी पारदर्शिता और आरक्षण व्यवस्था से जोड़ते हुए निष्पक्ष कार्रवाई बताया है, जबकि AIMIM की ओर से इस फैसले के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है।कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रोशन शेख इस आदेश को अदालत में चुनौती देती हैं तो अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल बीएमसी का आदेश प्रभावी हो चुका है और गोवंडी वार्ड की प्रतिनिधित्व व्यवस्था में बदलाव की स्थिति बन गई है।

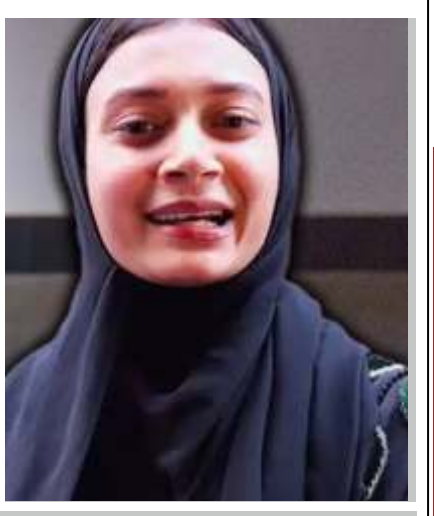

भारी बारिश से कई राज्यों में 10 से अधिक लोगों की मौत

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वर्ष मानसून निर्धारित तिथि 8 जुलाई से एक दिन की देरी से पूरे भारत में सक्रिय हुआ, लेकिन इसके पहुंचते ही कई राज्यों में तेज और लगातार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी। बीते बृहस्पतिवार को हुई मूसलाधार वर्षा के कारण उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी राज्यों के अनेक शहरों में सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गईं, निचले इलाकों में पानी भर गया और यातायात व्यवस्था घंटों तक बाधित रही। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर पड़े और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। भारी वर्षा के चलते मकानों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। विभिन्न राज्यों से बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई हैं, जिनमें अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। प्रशासन ने कई संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दल तैनात किए हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार जुलाई के शुरुआती नौ दिनों में देशभर में 101.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य औसत वर्षा 73.8 मिलीमीटर होती है। यानी इस बार सामान्य से काफी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई है और रेड तथा ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से भारत-ऑस्ट्रेलिया ने दिया खेल सहयोग का नया संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) का दौरा कर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल सहयोग को नई दिशा देने की पहल की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ उन्होंने संयुक्त रूप से 'इंडिया-ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोऑपरेशन रोडमैप' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दोनों देशों के युवा खिलाड़ियों, क्रिकेट दिग्गजों और खेल प्रशासकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया।एमसीजी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मैदान केवल क्रिकेट का स्टेडियम नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साझा खेल इतिहास और भावनात्मक रिश्तों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "एमसीजी में कदम रखना किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं जगाता है—भारत-ऑस्ट्रेलिया मुकाबलों का रोमांच और दोनों देशों के लोगों के बीच क्रिकेट के प्रति साझा जुनून।" उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि आज यहां किसी आखिरी ओवर के

रोमांच का दबाव नहीं, बल्कि मित्रता, सहयोग और भविष्य के खिलाड़ियों के सपनों का उत्सव है।नए स्पोर्ट्स रोडमैप के तहत दोनों देश खेल विज्ञान, कोचिंग, प्रतिभा विकास, महिला खेलों को बढ़ावा, खेल अवसंरचना, खेल प्रबंधन तथा खिलाड़ियों के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। इसके अलावा ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में भी साझा प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिकेट से आगे बढ़कर हॉकी, तैराकी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में भी यह साझेदारी दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खोलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से मजबूत रणनीतिक संबंधों में खेल सहयोग का यह नया अध्याय युवाओं को जोड़ने और दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा संदेश, महासभा ने भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित

विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह प्रस्ताव तालिबान पर कूटनीतिक दबाव को और बढ़ाएगा। यद्यपि महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी वे वैश्विक जनमत और सदस्य देशों की सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है। शुक्रवार को पारित इस प्रस्ताव में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की अपील की गई है। साथ ही तालिबान से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप शासन व्यवस्था अपनाने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में बड़ी संख्या में सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि कुछ देशों ने मतदान से दूरी बनाई। हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे अफगानिस्तान के मुद्दे पर वैश्विक समुदाय की एकजुट राय और मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बालिकाओं को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से वंचित करना, कई क्षेत्रों में उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाना और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित करना संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों तथा सार्वभौमिक मानवाधिकारों के विरुद्ध है। महासभा ने तालिबान प्रशासन से आग्रह किया कि वह महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से काम करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने और सामाजिक जीवन में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान के भविष्य का निर्माण तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवतियों, को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं।संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी देश का स्थायी विकास और आर्थिक पुनर्निर्माण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं हो सकता। कई सदस्य देशों ने महासभा में अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध केवल व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि यह अफगानिस्तान के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। कई प्रतिनिधियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगान जनता के लिए मानवीय सहायता जारी रखने की अपील भी की।दूसरी ओर, तालिबान प्रशासन ने एक बार फिर अपने फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि उसकी नीतियां अफगानिस्तान की सांस्कृतिक परंपराओं और इस्लामी मूल्यों के अनुरूप हैं। हालांकि अधिकांश सदस्य देशों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर महिलाओं के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से यह कहता रहा है कि महिलाओं के अधिकारों की बहाली अफगानिस्तान के साथ सामान्य राजनयिक और आर्थिक संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण शर्त है।

जर्मनी ने अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल खरीदने का किया ऐलान

यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और सामरिक घटनाक्रम सामने आया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने घोषणा की है कि उनकी सरकार अमेरिका से लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज़ मिसाइलें खरीदने की योजना पर आगे बढ़ रही है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यूरोप में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और नाटो सदस्य देश अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहे हैं।जर्मन सरकार का कहना है कि आधुनिक हथियार प्रणाली से देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और नाटो की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। टॉमहॉक मिसाइलें लंबी दूरी तक अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम मानी जाती हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस खरीद से जर्मनी की सामरिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और वह यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में पहले से अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेगा।हालांकि इस फैसले पर घरेलू राजनीति में भी बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों और शांति समर्थक संगठनों ने सरकार से इस रक्षा सौदे की आवश्यकता और संभावित आर्थिक प्रभाव पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के लिए संसाधनों का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।दूसरी ओर नाटो से जुड़े रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में यूरोपीय देशों द्वारा रक्षा निवेश बढ़ाना स्वाभाविक कदम है। यूक्रेन संकट और पूर्वी यूरोप में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बाद अधिकांश सदस्य देश अपनी रक्षा तैयारियों को नई दिशा दे रहे हैं।

इंडियन यूथ कांग्रेस ने सरकार की 20% इथेनॉल-मिश्रित ईंधन नीति (E20 पेट्रोल) के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया

जींद-सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन सेवा को मंजूरी

रेल मंत्रालय ने भारत की पहली रोज़ाना चलने वाली हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन सर्विस को मंज़ूरी दे दी है, जो जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। सूत्रों के अनुसार, यह सेवा ट्रेन संख्या 74010/74009 के रूप में चलेगी, जिसमें जिंद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भम्बेवा, ईशापुर खीरी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभरा, लाठ, मोहना (हरियाणा) और बड़वासनी में वाणिज्यिक स्टॉप होंगे। जून में, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स का आकलन करने के लिए दिल्ली और जींद के बीच इमरजेंसी ब्रेकिंग दूरी और ट्रेन के हिलने-डुलने (ऑसिलेशन) पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ट्रायल रन किया गया था। भारतीय रेलवे ने मई में नॉर्दर्न रेलवे के जींद-सोनीपत सेक्शन पर 10-कार वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल-बेस्ड ट्रेनसेट शुरू करने को मंज़ूरी दी थी। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ट्रेनसेट जल्द ही शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है और 1200 KW के हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके 75 kmph की अधिकतम रफ़्तार से चलेगी। इस पहल का मकसद साफ़-सुथरे और ज़्यादा ऊर्जा-कुशल रेल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बिजली बनाती है, जिसमें सिर्फ़ जल-वाष्प (water vapour) ही निकलता है। इस वजह से यह पारंपरिक फॉसिल फ्यूल-आधारित ट्रैक्शन सिस्टम का एक साफ़-सुथरा विकल्प है। इस प्रोजेक्ट के साथ, भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन से चलने वाले रेल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहे हैं।

ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने शरणार्थी नीति को बताया गैरकानूनी, सरकार को बड़ा झटका

ब्रिटेन की सरकार को अवैध प्रवासन रोकने की नीति पर बड़ा कानूनी झटका लगा है। शुक्रवार को लंदन हाई कोर्ट ने फ्रांस-ब्रिटेन के "वन-इन, वन-आउट" शरणार्थी समझौते से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सरकारी नीति को गैरकानूनी करार दिया। अदालत ने कहा कि सरकार ने संभावित मानव तस्करी के पीड़ितों को अपने मामलों की दोबारा समीक्षा कराने का अवसर छीन लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।यह मामला पांच शरणार्थियों द्वारा दायर याचिका के बाद अदालत पहुंचा था। इन लोगों का दावा था कि उन्हें मानव तस्करी का शिकार होने के बावजूद पर्याप्त कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई और उन्हें फ्रांस वापस भेजने की प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि सरकार की संशोधित गाइडलाइन के कारण कई मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार किए बिना ही निर्णय लिए गए।हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, विशेषकर तब जब मामला मानव तस्करी और शरण जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा हो। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2025 में प्रारंभिक स्तर पर खारिज किए गए बड़ी संख्या में मामलों को बाद में समीक्षा के दौरान पलट दिया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि पुनर्विचार की प्रक्रिया आवश्यक है।ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि सरकार इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी। सरकार का तर्क है कि अवैध प्रवासन पर नियंत्रण और मानव तस्करी के नेटवर्क को रोकना उसकी प्राथमिकता है, इसलिए सीमा सुरक्षा के लिए सख्त नीतियां आवश्यक हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर ब्रिटेन की आव्रजन नीति के साथ-साथ फ्रांस के साथ हुए प्रवासन समझौते पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में सरकार की अपील और इस पर होने वाली राजनीतिक बहस पूरे यूरोप में प्रवासन नीति को लेकर नई चर्चा को जन्म दे सकती है।

अमेरिका ने कनाडा के आयात पर 35% शुल्क लगाने की घोषणा

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों में शुक्रवार को नया तनाव देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 1 अगस्त 2026 से कनाडा से आयात होने वाले कई उत्पादों पर 35 प्रतिशत आयात शुल्क (टैरिफ) लगाया जाएगा। व्हाइट हाउस के अनुसार यह निर्णय अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और सीमा पार अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है। इस घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से कनाडा के साथ व्यापारिक असंतुलन बना हुआ है और अब अमेरिकी उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक हो गया है। अधिकारियों के अनुसार यह शुल्क लकड़ी, इस्पात, एल्यूमीनियम और कुछ कृषि उत्पादों सहित कई श्रेणियों पर लागू हो सकता है। हालांकि अंतिम सूची अभी जारी की जानी बाकी है।कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उनका देश अपने उद्योगों और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका का सबसे विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच दशकों से मजबूत आर्थिक संबंध हैं। ऐसे में एकतरफा टैरिफ लगाने का निर्णय दोनों देशों के कारोबार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह निर्णय लागू होता है तो उत्तर अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र पर इसका असर पड़ने की आशंका है। कई उद्योग संगठनों ने भी दोनों सरकारों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।वैश्विक बाजारों ने भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी है। निवेशकों को आशंका है कि यदि दोनों देशों के बीच व्यापारिक विवाद और गहराता है तो इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और वित्तीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संभावित वार्ता और कनाडा की प्रतिक्रिया पर दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी।

संपादक की कलम से

देश में आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर एक बार फिर बड़ा संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान और गुजरात में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास केवल दो राज्यों तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की विकास रणनीति का संकेत भी है। सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, मेट्रो और हवाई अड्डों जैसी परियोजनाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। यदि इनका समय पर और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, तो रोजगार सृजन, निवेश और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलती है।पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की है। इसका असर राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे आधुनिकीकरण, बंदरगाहों और ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई भी दे रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह निवेश आवश्यक है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों की लागत घटती है, व्यापार बढ़ता है और आम नागरिकों का जीवन भी आसान होता है।हालांकि केवल परियोजनाओं की घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। देश ने ऐसे अनेक उदाहरण भी देखे हैं, जहां बड़े-बड़े शिलान्यास वर्षों तक अधूरे पड़े रहे या लागत कई गुना बढ़ गई। इसलिए किसी भी परियोजना की वास्तविक सफलता उसके समयबद्ध निर्माण, गुणवत्ता और जनता को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ से तय होती है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि घोषित योजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हों और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।विपक्ष का यह दायित्व भी है कि वह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहे, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही पर रचनात्मक निगरानी रखे। लोकतंत्र में विकास और जवाबदेही एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां सरकार विकास का रोडमैप तैयार करती है, वहीं विपक्ष और स्वतंत्र संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही दिशा में हो।भारत आज विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे समय में आधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश भविष्य की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ सुशासन, पारदर्शिता और पर्यावरणीय संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। विकास का उद्देश्य केवल आंकड़ों में वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में वास्तविक सुधार होना चाहिए।सरकार और विपक्ष दोनों को यह समझना होगा कि विकास परियोजनाएं चुनावी राजनीति का साधन बनने के बजाय राष्ट्रीय निर्माण का माध्यम बनें। यदि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे, रोजगार बढ़े और संसाधनों का पारदर्शी उपयोग हो, तभी भारत का विकास मॉडल वास्तव में समावेशी और टिकाऊ कहलाएगा।

विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया मास्टर प्लान

11 जुलाई की रणनीति बैठक पर टिकी निगाहें

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां समय से पहले शुरू कर दी हैं। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने के उद्देश्य से 11 जुलाई को लखनऊ में महत्वपूर्ण रणनीति बैठक आयोजित की जा रही है। इसी बैठक को लेकर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

लोकसभा और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को सामने आई जानकारी के अनुसार पार्टी ने 11 जुलाई को लखनऊ में होने वाली प्रदेश स्तरीय रणनीति बैठक के लिए विस्तृत एजेंडा तैयार कर लिया है। इस बैठक में संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, सदस्यता अभियान, लाभार्थी संपर्क और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। यह पहली बार है जब भाजपा ने 2027 के चुनावी अभियान की औपचारिक रूपरेखा तय करने की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया है।बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सहित प्रदेश के सभी प्रमुख पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला इकाइयों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व का लक्ष्य अगले डेढ़ वर्ष में प्रत्येक बूथ को सक्रिय करना और नए मतदाताओं के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाना है। इसके साथ ही विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों को भी अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी ताकि चुनावी तैयारी समय से पहले पूरी की जा सके।सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार केवल चुनावी प्रचार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि गांव, कस्बों और शहरों में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाने की योजना बना रही है। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों तक दोबारा पहुंच बनाने, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने तथा सोशल मीडिया नेटवर्क को और मजबूत करने पर भी बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष की रणनीति का मुकाबला करने के लिए अलग कार्ययोजना तैयार की जा रही है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने 2027 की तैयारी सामान्य से काफी पहले शुरू कर दी है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी चुनावी संगठन को मजबूत करने और पिछले चुनावों के अनुभवों का विश्लेषण कर नई रणनीति बनाने पर जोर दे रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अपने संगठन को सक्रिय करने में जुटी हैं, जिससे आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्म होने की संभावना है. 11 जुलाई की यह बैठक केवल संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे भाजपा के आगामी चुनावी अभियान के औपचारिक शुभारंभ के रूप में भी देखा जा रहा है। बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों का असर आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है।

राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन स्थगित, कांग्रेस की युवा रणनीति पर उठे सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आयोजित होने वाले छात्र सम्मेलन फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। शुक्रवार को इस संबंध में सामने आए घटनाक्रम ने कांग्रेस के राजनीतिक अभियान को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पार्टी ने इन सम्मेलनों के माध्यम से युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की योजना बनाई थी। इन कार्यक्रमों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, प्रश्नपत्र लीक, बेरोजगारी, उच्च शिक्षा की चुनौतियों और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर राहुल गांधी को सीधे संवाद करना था। इन सम्मेलनों में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी।कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि संगठनात्मक कारणों और नई रणनीति के तहत इन्हें फिलहाल स्थगित किया गया है। पार्टी का कहना है कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी और अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। हालांकि, कार्यक्रमों के अचानक टलने से पार्टी के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई नेताओं का मानना है कि युवाओं से जुड़ा अभियान कांग्रेस की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसे निरंतर गति देना आवश्यक है।भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं के मुद्दों पर केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसके कार्यक्रमों में ही स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर होती तो कार्यक्रमों को बार-बार टालने की नौबत नहीं आती।दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण पूरी तरह प्रशासनिक और संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद अभियान जारी रहेगा और आने वाले दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवाओं और छात्रों को अपने अभियान का प्रमुख आधार बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इन सम्मेलनों का स्थगित होना अस्थायी झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन यदि पार्टी शीघ्र नई तारीखों की घोषणा कर प्रभावी ढंग से अभियान शुरू करती है, तो यह रणनीति फिर गति पकड़ सकती है।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन,सभी दलों को दिया न्योता

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल विपक्षी दलों ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया है। उनका कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा किसी एक दल का राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक सम्मान से जुड़ा विषय है।फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी सीमित हुई है। उनका मानना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और जनता को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस मांग के समर्थन में एकजुट हों।इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दल इस प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि विभिन्न दल इस मंच पर साथ आते हैं, तो यह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश होगा।विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है और इस पर केंद्र सरकार भी समय-समय पर सकारात्मक संकेत देती रही है। ऐसे में 20 जुलाई का प्रस्तावित प्रदर्शन इस विषय पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाले दिनों में विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया और इस आंदोलन में उनकी भागीदारी पर देशभर की नजर रहेगी, क्योंकि इससे जम्मू-कश्मीर की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श भी प्रभावित हो सकता है।

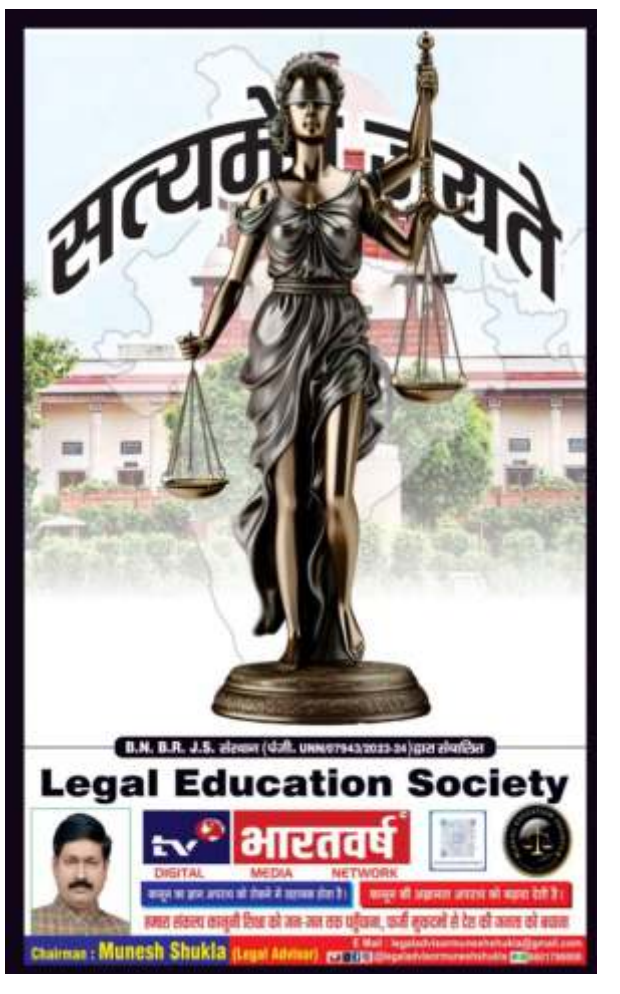

ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम खास क्यों?

ऑस्ट्रेलिया का विशाल उच्च-गुणवत्ता यूरेनियम भारत के बढ़ते न्यूक्लियर कार्यक्रम के लिए जरूरी है. एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के कारण लंबा इनकार 2014 के समझौते के बाद समाप्त हुआ, जो रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है.

ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम खास होने की वजह वहां की सरकार की पॉलिसी है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम आपूर्ति का मुद्दा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखने वाला देश है, लेकिन लंबे समय तक भारत को इसकी आपूर्ति से इनकार करता रहा. 2014 के समझौते ने इस राह को खोल दिया.

ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कुल ज्ञात रिकवरेबल यूरेनियम भंडार का करीब 28-30 प्रतिशत हिस्सा रखता है. यह मात्रा अन्य किसी भी देश से ज्यादा है. मुख्य रूप से साउथ ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डैम, नॉर्दर्न टेरिटरी के रेंजर और जाबिलुका तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खदानों में यह पाया जाता है. ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की गुणवत्ता भी बेहतर मानी जाती है. अयस्क अक्सर हाई-ग्रेड होता है, जिससे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद है. इसमें अशुद्धियां कम होती हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए उपयुक्त है. स्थिर राजनीतिक माहौल, मजबूत लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय गैर-प्रसार नीतियों का पालन करने वाला देश होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षित आपूर्तिकर्ता माना जाता है. कई अन्य यूरेनियम उत्पादक देशों में राजनीतिक अस्थिरता या सुरक्षा जोखिम होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है. यह विश्वसनीयता इसे खास बनाती है. रासायनिक रूप से यह सामान्य प्राकृतिक यूरेनियम है – ज्यादातर U-238 और थोड़ी मात्रा में U-235. भारत के पास यूरेनियम के भंडार सीमित हैं और वे भी ज्यादातर कम-ग्रेड के हैं. देश का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, खासकर प्रेसराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWR) को स्थिर यूरेनियम सप्लाई की जरूरत होती है. ⊙

रणनीतिक और आर्थिक महत्व

यह समझौता केवल ईंधन की आपूर्ति नहीं है. यह भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाई देता है. दोनों देश इंडो-पैसिफिक में शांती और स्थिरता चाहते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. घरेलू उत्पादन लगभग 400-500 टन सालाना है, जबकि जरूरत हजारों टन में है. ऑस्ट्रेलिया के पास 2040-47 तक भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता है. ⊙

स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

अश्वत बने भारत के 98वें ग्रैंडमास्टर

भारतीय शतरंज लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश के युवा खिलाड़ी दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रहने वाले 17 वर्षीय अश्वत एस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के 98वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। उनकी इस सफलता से भारतीय शतरंज जगत में खुशी की लहर है और अब देश के 100वें ग्रैंडमास्टर बनने की दिशा में भी कदम तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, अश्वत एस ने 2026 पुणे अंतरराष्ट्रीय ग्रैंडमास्टर राउंड रॉबिन शतरंज प्रतियोगिता में अपना अंतिम ग्रैंडमास्टर मानक हासिल किया। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में उन्हें ग्रैंडमास्टर बनने के लिए जीत की जरूरत थी और उन्होंने इस चुनौती को शानदार तरीके से पूरा किया। अश्वत ने काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के फिडे मास्टर कन्नन वैद्यनाथन को हराकर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि ग्रैंडमास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा निर्धारित तीन ग्रैंडमास्टर मानक पूरे करने के साथ

निर्धारित रेटिंग भी हासिल करनी होती है। अश्वत एस ने अंतिम मुकाबले में जीत के साथ यह सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं और अब आधिकारिक रूप से भारत के 98वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। गौरतलब है कि अश्वत एस का इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा। उन्होंने कुल 9 दौर में 7 अंक हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 6 मुकाबलों में जीत, 2 मुकाबले बराबरी पर समाप्त किए और उन्हें केवल 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान भी हासिल किया है।

20 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की घोषणा

अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों के दौरान भारत की 20 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कमान संभालेंगी। सलीमा की कप्तानी में ही भारत ने पिछले महीने न्यूजीलैंड में एफआईएच नेशंस कप में अपराजेय रहकर खिताब जीता था और इसके साथ ही प्रो लीग में अपनी वापसी सुनिश्चित की थी। भारतीय टीम के मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने चयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसी टीम है जिसमें जूनियर, अनुभवी और सीनियर खिलाड़ियों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। उन्होंने बताया कि टीम के ये सभी खिलाड़ी लगातार एक-दूसरे के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। टीम में गोलकीपर की भूमिका पद्मश्री से सम्मानित सविता और बिछू देवी खारीबम निभाएंगी। रक्षापंक्ति यानी डिफेंस की जिम्मेदारी सुशीला चानू, इशिका चौधरी और ज्योति संभालेंगी। इनके साथ ही एफआईएच नेशंस कप के जरिए सीनियर टीम में पदार्पण करने वाली लालथांटलुआंगी और शिल्पी डबास को भी टीम में स्थान मिला है। मिडफील्ड विभाग में कप्तान सलीमा टेटे के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिटा टोप्पो, नेहा और दीपिका सोरेंग को शामिल किया गया है। वहीं फॉरवर्ड लाइन यानी अग्रिम पंक्ति में लालरेम्सियामी, रुतुजा पिसाल, नवनीत कौर, बलजीत कौर, इशिका, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका मौजूद हैं। नेशंस कप में सबसे ज्यादा छह गोल दागने वाली दीपिका टीम के आक्रमण की मुख्य कड़ी होंगी। कोच शोर्ड मारिन ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस समूह ने खुद को पूरी तरह फिट और शानदार फॉर्म में साबित किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह भारतीय टीम एशियाई खेलों की कड़ी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

ब्रूनो फर्नांडिस बोले- 'बेहद दुखी, निराश और हताश हूं'

विश्व कप में मजबूत खिलाड़ियों से सजी पुर्तगाल टीम को टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उसका सफर अंतिम 16 के दौर में ही समाप्त हो गया। स्पेन के खिलाफ करीबी मुकाबले में मिली हार के बाद पुर्तगाल के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस ने अपनी निराशा और भावनाएं सार्वजनिक रूप से साझा की। मौजूद जानकारी के अनुसार, स्पेन ने अंतिम 16 के मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मैच का फैसला अंतिम समय में मिकेल मेरिनो द्वारा किए गए गोल से हुआ। पूरे मुकाबले के दौरान दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन लंबे समय तक कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। अंत में स्पेन ने अवसर का फायदा उठाकर जीत अपने नाम कर ली। हार के बाद ब्रूनो फर्नांडिस ने सामाजिक मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने लिखा कि वह बेहद दुखी, निराश और हताश हैं। उनके अनुसार इस टीम की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के बीच वर्षों में बना मजबूत तालमेल उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता था। उन्होंने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और सहयोगी सदस्यों ने पूरे विश्व कप के दौरान पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। साथ ही उन्होंने पुर्तगाल के सभी समर्थकों का लगातार मिले विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। गौरतलब है कि इस विश्व कप में पुर्तगाल को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा सितारे भी शामिल थे। दूसरी ओर स्पेन के पास लामिन यामाल, मिकेल ओयारजाबाल और अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों को इस मुकाबले में कई गोल देखने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों टीमों की मजबूत रक्षापंक्ति के कारण मुकाबला काफी संतुलित रहा। इस जीत के साथ स्पेन ने विश्व कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। बता दें कि स्पेन विश्व कप में लगातार छह मुकाबलों तक बिना कोई गोल खाए जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेन की मजबूत रक्षापंक्ति और अनुशासित खेल इस टूर्नामेंट में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं।

पुणे में भारी बारिश और सड़कें बंद होने के बावजूद एक कर्मचारी को उसके मैनेजर ने छुट्टी देने से मना कर दिया. मैनेजर ने उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा या उबर से ऑफिस आने की सलाह दी. वॉट्सअप चैट का स्क्रीनशॉट रेडिट पर वायरल होने के बाद लोग मैनेजर की आलोचना कर रहे हैं.

कोई मैनेजर के रवैये को गलत बता रहा है, तो कोई कंपनी के वर्क कल्चर पर सवाल उठा रहा है. (Photo: ITG)

बारिश में मांगी छुट्टी तो भड़का बॉस, कहा- कैब से आओ

जान पहले या फिर जॉब?

सर... बाहर इतनी बारिश है कि सड़कें डूब गई हैं. आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. अगर आपको लगता है कि इस मेसेज के जवाब में बॉस कहेगा, कोई बात नहीं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, तो आप गलत हैं. पुणे में एक कर्मचारी के साथ ठीक इसका उल्टा हुआ. छुट्टी मांगने पर मैनेजर ने ऐसा जवाब दिया कि अब उसकी वॉट्सअप चैट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इतना ही नहीं, कर्मचारी इस बात तक सोचने लगा कि क्या ऐसी नौकरी छोड़ देना ही बेहतर होगा? दरअसल, पुणे में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं. जगह-जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. ऐसे में एक कर्मचारी ने अपने मैनेजर को वॉट्सअप पर मैसेज भेजकर बताया कि खराब मौसम और बंद रास्तों की वजह से वह ऑफिस नहीं आ पाएगा. कर्मचारी ने बड़े ही सामान्य तरीके से लिखा- नमस्ते सर, बारिश और सड़क बंद होने की वजह से मैं आज काम पर नहीं आ सकूंगा. लेकिन इसके बाद जो जवाब आया, उसने सभी को चौंका दिया. मैनेजर ने लिखा- पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाओ. जब कर्मचारी ने फिर अपनी परेशानी बताई, तब भी मैनेजर का रुख नहीं बदला. ⊙

सोशल मीडिया छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती. इसलिए ऐसी परिस्थितियों में कंपनियों को नियमों से पहले इंसानियत दिखानी चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हर नौकरी वर्क फ्रॉम होम वाली नहीं होती. कई सेक्टर ऐसे हैं, जहां कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी होती है.

40 लाख की डायमंड रिंग निगल गया शख्स

सोचिए, कोई शख्स ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आए, घंटों तक अंगूठियां देखे और फिर मौका मिलते ही लाखों रुपये की हीरे की अंगूठी... जेब में नहीं, बल्कि सीधे निगल जाए. सुनने में यह किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन लंदन में ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि एक शख्स लंदन के मशहूर हैटन गार्डन इलाके की एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर पहुंचा. उसने करीब दो घंटे तक अलग-अलग डायमंड रिंग्स देखीं. दुकान के कर्मचारियों को लगा कि वह शादी के लिए अंगूठी पसंद कर रहा है, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और ही थे. ⊙

करोड़पति बनने के बाद भी रिटायरमेंट से लगता है डर

क्या आपको लगता है कि अगर किसी इंसान के पास 10 या 11 करोड़ रुपये की संपत्ति हो जाए, तो वह आराम से नौकरी छोड़कर जिंदगी का आनंद ले सकता है? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब 'हां' होगा. लेकिन हाल ही में सामने आई एक कहानी ने लोगों की इस सोच को बदल दिया है. 48 साल के एक टेक प्रोफेशनल ने बताया कि उसने मेहनत और समझदारी से निवेश करके करीब 11 करोड़ रुपये की संपत्ति बना ली है. इसके बावजूद वह नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. ⊙

फाइनेंसियल एक्सपर्ट भी अक्सर कहते हैं कि रिटायरमेंट का फैसला सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर नहीं लेना चाहिए. (Photo: ITG)

बारिश में ये जुगाड़ वायरल

स्कूटी में पाइप क्यों लगवा रहे लोग?

मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों की गलियों में पानी भरने लगा है. इन पानी से भरी सड़कों पर कुछ स्कूटी और बाइक में एक अजीब जुगाड़ के साथ फर्राटे भरते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें स्कूटी और बाइक की साइलेंसर में एक पाइप लगा हुआ दिखाई दे रहा है. यह जुगाड़ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसे में समझते हैं कि आखिर लोग अपने स्कूटी और बाइक की साइलेंसर में ये छोटा सा पाइप क्यों लगवा रहे हैं. क्योंकि, मुंबई में जहां बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है. लोग स्कूटी में ऐसे पाइप लगाकर घूम रहे हैं. इन दिनों मानसून आने के साथ ही झमाझम बारिश हो रही है. दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर में भी खूब बादल बरसे हैं. दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के कई इलाकों में तो काफी पानी भर गया है. ऐसे में बाइक और स्कूटी से चलने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी है. ⊙

बोरिंग जोक्स और खराब VFX ने बिगाड़ा खेल

बॉलीवुड में कॉमेडी फ्रेंचायजी बड़ी सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही का जादू ऑडियंस पर चलता है. हाल ही में अक्षय की वेलकम टू द जंगल ने वो चीज दोहराने की कोशिश की.

अब अजय देवगन भी 'धमाल 4' लाए हैं, जो एक और जबरदस्त फ्रेंचायजी फिल्म है. साल 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले 19 सालों में इसके तीन पार्ट्स आ चुके हैं.

खास बात ये है कि तीनों पार्ट्स लोगों को पसंद आए. धमाल 4 को लेकर उम्मीदें तभी से बंधने लगी थीं जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था. उसे काफी पसंद किया गया था. ट्रेलर में जो कॉमेडी पंच थे, वो सही से लैंड भी हो रहे थे. लेकिन वो कहावत हैं ना कि किसी चीज से ज्यादा उम्मीदें लगा लो, तो उसके टूट जाने पर बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म धमाल 4 के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है. आइए, आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा. धमाल फ्रेंचायजी एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कई सारी अनोखी सिचुएशन्स के अंदर ह्यूमर डाला जाता है. ⊙

एक ही जगह मिलेगा स्वाद, पर्यटन और तकनीक का अनूठा संगम

लखनऊ में दौड़ेंगे डबल डेकर फूड ट्रक, 24 जुलाई तक मांगी गईं निविदाएं

उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ में पर्यटन को नई पहचान देने के लिए अत्याधुनिक डबल डेकर फूड ट्रक शुरू करने जा रही है। पहले चरण में इनका संचालन नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान और डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में किया जाएगा। बाद में इस परियोजना का विस्तार प्रदेश के प्रमुख पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण खानपान के साथ उत्तर प्रदेश की समृद्ध खाद्य संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा अनुभव उपलब्ध कराना है। यूनेस्को द्वारा लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिलने के बाद फूड ट्रकों के मेन्यू में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के तहत प्रदेश के पारंपरिक और स्थानीय व्यंजनों को प्रमुखता दी जाएगी। डबल डेकर फूड ट्रकों में डिजिटल पीओएस सिस्टम, यूपीआई और कार्ड भुगतान, एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी, क्यूआर कोड आधारित ग्राहक फीडबैक और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं होंगी। सभी लेनदेन डिजिटल माध्यम से होंगे, जिससे पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। फूड ट्रक का ऊपरी हिस्सा पर्यटकों के लिए एक डिजिटल अनुभव केंद्र होगा, जहां एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी) और वीआर (वर्चुअल रियलिटी) तकनीक के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटन स्थलों और जैव विविधता

का अनुभव कराया जाएगा। इसके साथ ही एलईडी आधारित डिजिटल हेरिटेज गैलरी, इमर्सिव ऑडियो सिस्टम और ईको-डाइनिंग लाउंज भी उपलब्ध रहेगा। परियोजना को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए फूड ट्रकों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। वहीं खाद्य पैकेजिंग में पत्तल, बांस, मिट्टी और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके। इस परियोजना के संचालन के लिए निजी सहभागिता के तहत निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इच्छुक कंपनियां 24 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगी। सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पर्यटन, स्थानीय व्यंजनों और आधुनिक तकनीक को एक मंच पर लाकर पर्यटकों को नया अनुभव प्रदान करना है।

पेंशनरों को एक जनवरी से 60 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता राहत देने का प्रस्ताव मंजूर

आवास-विकास परिषद की बोर्ड बैठक संपन्न

उत्तर प्रदेश आवास -विकास परिषद की बोर्ड बैठक में परिषद कार्मिकों , पेंशनरों को एक जनवरी से 60 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता राहत अनुमन्य किये जाने को लेकर आये प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी है। गुरुवार देर शाम तक चली इस बैठक में कुल सात प्रस्ताव को सभी सदस्यों की रजामंदी से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। परिषद की बोर्ड बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिए जा रहे स्थानीय भत्ता की धनराशि को भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इसके साथ अधिशासी अभियंता की नियुक्ति को लेकर रखे गए प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान करते हुए नियमावली संशोधित किये जाने की अनुमति दी गयी है। इसी तरह अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति दिये जाने के प्रस्ताव को भी सबकी सहमति से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इसके आलावा जनपद जौनपुर में कादीपुर में अधूरी पड़ी कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में गठित समितियों की आख्या के परीक्षणोपरांत सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों से रिकबरी के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया गया है। इसके चलते अब इस योजना के घोटालेबाजों से आवास - विकास घोटाले की रकम रिकबरी कर पूरा करेगा। यही नहीं अयोध्या में बाजार पूरक योजना में हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में विचाराधीन याचिका पर पारित आदेश के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यूटिलिटीज कार्य कराये जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इसी तरह बैठक में परिषद की योजना के ले-आउट में सृजित सम्पत्तियों पर जोनिंग रेगुलेशन 2025 के मुताबिक पर्यटन इकाई के लिए होटल उपयोग प्रक्रिया के निर्धारण प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गयी है। परिषद की 276 वीं बोर्ड की बैठक प्रशासनिक भवन के सभागार में अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें परिषद के आवास आयुक्त बलकार सिंह और सचिव नीरज शुक्ला समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे।

45 देशों के बाल गणितज्ञों के बीच प्रतिभा दिखाएगा सीएमएस का छात्र दल, हांगकांग के लिए रवाना

लखनऊ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) का छह सदस्यीय छात्र ल अंतरराष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता ाइमरी मैथमेटिक्स वर्ल्ड कॉन्टेस्ट' भाग लेने के लिए हांगकांग रवाना गया है। 15 से 19 जुलाई तक ायोजित होने वाली इस प्रतियोगिता विश्व के लगभग 45 देशों के 14 र्ष से कम आयु के छात्र अपनी णितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तियोगिता का आयोजन हांगकांग की तिष्ठित सामाजिक-शैक्षिक संस्था पो उँग कुक द्वारा किया जा रहा है। पीएमएस के हेड कम्युनिकेशन्स ऋषि त्रा ने बताया कि भारतीय दल में पीएमएस महानगर कैंपस के अहान टियार, इंदिरा नगर प्रथम कैंपस के ोहम्मद समद, गोमती नगर प्रथम ंपस के आरुष निगम तथा अलीगंज थम कैंपस की छात्रा अलिश्बा ादिक शामिल हैं। छात्र दल का नेतृत्व लीगंज प्रथम कैंपस की वरिष्ठ क्षिका श्रेया गुप्ता कर रही हैं, जबकि गोमती नगर प्रथम कैंपस के शिक्षक अबू साद डिप्टी लीडर के रूप में दल के साथ गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के छात्रों में गणित के प्रति रुचि विकसित करना, उनकी तार्किक क्षमता को बढ़ावा देना तथा विभिन्न देशों के छात्रों के बीच गणितीय ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान कराना है। इस मंच पर सीएमएस के छात्रों को दुनिया के विभिन्न देशों के बाल गणितज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। ऋषि खन्ना ने कहा कि यह प्रतियोगिता छात्रों को केवल प्रतिस्पर्धा का अवसर ही नहीं देती, बल्कि उन्हें गणित की नवीन अवधारणाओं, वैश्विक शिक्षण पद्धतियों और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक वातावरण से भी परिचित कराती है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के छात्रों के बीच संवाद और सहयोग के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना को भी प्रोत्साहन मिलता है।

लखनऊ पूर्वी विधानसभा में 91.52 लाख रुपये से 9 पार्कों का विकास

लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण को नई गति मिली है। विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव ने गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के माध्यम से लगभग 91.52 लाख रुपये की लागत से विकसित पांच पार्कों का लोकार्पण किया, जबकि चार नए पार्कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इंदिरा नगर वार्ड में करीब 57.91 लाख रुपये की लागत से पांच पार्कों का कायाकल्प किया गया है। इन पार्कों में ओपन जिम, बच्चों के झूले, पाथवे, इंटरलॉकिंग टाइल्स, बेंच, बाउंड्री वॉल की मरम्मत, रंगाई-पुताई, आकर्षक पेंटिंग और हरित सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कराए गए हैं। इसके अलावा इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अटल पार्क, इस्माइलगंज प्रथम वार्ड के इन्क्लेव पार्क संख्या-2 तथा मैथिलीशरण गुप्त वार्ड के दो पार्कों में विकास कार्यों का

शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि पार्क केवल मनोरंजन के स्थल नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज, स्वच्छ पर्यावरण और सामाजिक समरसता के केंद्र होते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाली किसी भी शहर की पहचान है और पार्क नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की प्रेरणा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ का तेजी से विकास हो रहा है। सड़क, फ्लाईओवर और अन्य आधारभूत परियोजनाओं के साथ पार्कों के विकास, ओपन जिम, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के माध्यम से शहर को और अधिक हरित एवं सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि पूर्वी विधानसभा में विकास कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुकरैल नदी संरक्षण, उर्मिला वन के विकास, हरित क्षेत्रों के विस्तार और व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से क्षेत्र को आदर्श हरित विधानसभा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए प्रत्येक नागरिक से पौधारोपण और उसके संरक्षण का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने पार्कों के विकास के लिए विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन कार्यों से बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र का वातावरण अधिक स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनेगा।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत

-बेटे के सामने हुआ दर्दनाक हादसा
-बाजार से खरीदारी कर लौट रहे थे मां-बेटे, ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा
ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिस ने कब्जे में ली

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो) फतेहपुर चैरासी उन्नाव। बाजार से घर वापस लौट रहे बाइक सवार मां बेटे ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से गिर गए,जिससे बाइक सवार मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को सीएचसी लाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने अस्पताल के मेमो पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

क्षेत्र की ग्राम पंचायत सूसूमऊ के मजरा ग्राम भवानीखेड़ा निवासी लगभग पचास वर्षीय सुमन देवी पत्नी स्वव भैरव प्रसाद गुरुवार को अपने बड़े बेटे शिवम के साथ बाइक से कस्बा फतेहपुर चैरासी की बाजार खरीदारी करने आई थी। जहां से लगभग 3 बजे यह लोग घर वापस जा रहे थे, अभी मां बेटे बूचागाड़ा जमुनिहा मार्ग पर ग्राम जमरुद्दीनपुर के पास ही पहुंचे थे तभी आगे जा रही मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से बाइक सवार गिर गए। जिससे बाइक पर पीछे बैठी सुमन देवी ट्रैक्टर ट्राली के पहिए के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गयी। घायल को राजगीरों की मदद से फतेहपुर चैरासी सी एच सी लाया गया जहां डॉक्टर ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। मृतका अपने पीछे दो पुत्र शिवम एवं बेटा सिंह को रोता बिलखता छोड़ गई है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस में अस्पताल के मेमो पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया है कि ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है,तथा अस्पताल के मेमो पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग, माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन

उन्नाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को जिलाध्यक्ष हरिहर प्रसाद दीक्षित के नेतृत्व एवं जिला मंत्री रामशंकर के निर्देशन में जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) से मुलाकात कर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समस्याओं के शीघ्र निस्तारण को लेकर विस्तृत वार्ता भी हुई।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय मंत्री रमाशंकर मिश्रा (मुन्ना), सह-संयोजक चंद्र प्रकाश शुक्ला (छुन्ना), कुलदीप कुमार, सचिन त्रिपाठी, राम प्रकाश सोनी तथा मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

ज्ञापन में समय से वेतन भुगतान, पदोन्नति, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, व्यावसायिक शिक्षकों के सेवा विस्तार, नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में आच्छादित शिक्षकों की जीपीएफ खातों में धनराशि हस्तांतरित करने, आमेलित विषय विशेषज्ञों को ओपीएस का लाभ दिलाने तथा प्रवक्ता पद पर पदोन्नत शिक्षकों के वेतन निर्धारण सहित कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं।

इस पर डीआईओएस ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि जिले के 59 माध्यमिक विद्यालयों में से 51 विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण कोषागार भेज दिया गया है। शेष मामलों का भी शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा।प्रतिनिधिमंडल ने डीआईओएस कार्यालय में वित्त एवं लेखाधिकारी की अनियमित उपलब्धता और कार्यप्रणाली पर भी चिंता जताई। इस संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित एक अलग पत्र कार्यालय में सौंपा गया, जिसमें वित्त एवं लेखाधिकारी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा वेतन, एरियर, पेंशन स्वीकृति, जीपीएफ निकासी सहित अन्य वित्तीय मामलों का समयबद्ध निस्तारण कराने की मांग की गई। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की होगी।

राज्यमंत्री के सड़क वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा

-जनपद दौरे के दौरान मंत्री ने कहा था- सड़कें बनती हैं तो टूटती भी हैं
-कांग्रेस बोली- जनता सड़क बनाएगी तो टैक्स किस बात का

उन्नाव। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सड़क निर्माण और रखरखाव को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखा राजनीतिक हमला बोला है। पार्टी ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट जारी कर मंत्री के बयान को जनता के प्रति असंवेदनशील बताते हुए प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को जनपद दौरे पर आए राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह से गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त होने के संबंध में सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि, सड़कें बनती हैं तो टूटती भी हैं, खराब भी होती हैं। बारिश के समय कितनी भी अच्छी सड़क बने, थोड़ी-बहुत क्षति होती है। जो सड़कें खराब होती हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराया जाता है। इसी दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में आप अपने आप सड़क बना लो जैसी टिप्पणी भी की थी।

मंत्री के इसी बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट साझा की। पोस्ट में कहा गया कि प्रदेश सरकार के मंत्री जनता के टैक्स के पैसों से सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय लोगों को खुद सड़क बनाने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सरकार के कथित जीरो टॉलरेंस के दावों के विपरीत बताते हुए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और जवाबदेही का मुद्दा उठाया। पोस्ट में पार्टी ने सवाल किया कि यदि सड़क निर्माण की जिम्मेदारी भी जनता पर ही छोड़नी है, तो फिर जनता से भारी-भरकम टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है। साथ ही सरकार से सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की गई। मंत्री के बयान और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दल भी इसे लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

नवाबगंज टोल प्लाजा के पास ट्रक चालक से मारपीट,

चालक ने मोबाइल-नगदी लूटने का लगाया आरोप

नवाबगंज उन्नाव। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज टोल प्लाजा के पास देर रात ट्रक चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चालक ने दो बाइक सवार युवकों पर मारपीट करने के साथ मोबाइल फोन और नगदी लूट लेने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने लूट की घटना से इनकार करते हुए केवल मारपीट की सूचना मिलने की बात कही है।

फतेहपुर जिले के जहानाबाद निवासी अनिल दूध से भरा ट्रक लेकर उन्नाव से लखनऊ जा रहे थे। चालक के अनुसार, देर रात वह नवाबगंज टोल प्लाजा के पास ट्रक रोककर लघुशंका के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर डंडों से पीटा और उनका मोबाइल फोन व नगदी छीनकर फरार हो गए।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक से घटना की जानकारी ली। मामले में चैकी प्रभारी नवाबगंज मुकुल दुबे ने बताया कि लूट की सूचना नहीं मिली है। बीती रात ट्रक चालक के साथ बाइक सवार युवकों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

13 जुलाई को सीएम योगी करेंगे कानपुर-लखनऊ अवध एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

डीएम-एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, सुरक्षा

(ब्यूरो)उन्नाव। कानपुर-लखनऊ अवध एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जुलाई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है।

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बृहस्पतिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी कृति राज, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुशील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बैरिकेडिंग, प्रवेश एवं निकास मार्ग, वीआईपी मूवमेंट, पुलिस बल की तैनाती तथा भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने वाले मार्गों, पार्किंग व्यवस्था, यातायात डायवर्जन और वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, एंबुलेंस और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास भी कराया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए भी व्यापक पुलिस प्रबंधन किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी दी। जिला प्रशासन का लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे और अवध एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न कराना है।

एबीवीपी ने मनाया राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान

छात्र हित और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर हुआ मंथन

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो)बांगरमऊ उन्नाव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) लक्कुश नगर जिले की स्थानीय इकाई ने क्षेत्र के ग्राम साईंपुर सगौड़ा स्थित श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज में परिषद के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. नीरज गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना नौ जुलाई 1949 को छात्र शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से हुई थी। आज राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस युवाओं को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराने का अवसर है।

विकासार्थ विद्यार्थी के प्रांत संयोजक मानवेंद्र प्रताप ने कहा कि एबीवीपी स्थापना काल से ही छात्र हितों, शिक्षा सुधार और राष्ट्रहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि आज परिषद दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में पहचान रखती है। जिला संयोजक नवल दीप गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता प्राप्त की। यदि युवा उनके विचारों को अपनाएं तो वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं।

कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक विजय गुप्ता, नगर अध्यक्ष रोहित शर्मा, नगर मंत्री शांतनु गुप्ता, नगर सह मंत्री निमेष तिवारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

हाईवे पर मवेशियों से भरे ट्रक को लेकर बवाल, पुलिस ने वाहन रोककर की जांच

बजरंग दल के विरोध के बाद गदनखेड़ा बाईपास पर लगा जाम

स्वतंत्र भारत (ब्यूरो)उन्नाव। कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदनखेड़ा बाईपास के पास बृहस्पतिवार दोपहर मवेशियों से लदे एक ट्रक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रोककर पशुओं के परिवहन पर सवाल उठाए, जिसके बाद मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात संभालते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी।

राम और आस्था पर योगी का विपक्ष पर प्रहार हनुमानगढ़ी नमाज़ विवाद का किया ज़िक्र

आर्य संत वरुण दास महाराज ने कहा कि चंपत राय के समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए ही संत समाज ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अपना विचार रखा है क्योंकि राम जन्मभूमि के प्रति चंपत राय की वफादारी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही हैं और जो लोग अब आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की थी। अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग अब भगवान राम और आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही हाल ही में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की थी। अपनी आलोचना को और तेज़ करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा अयोध्या के विकास का विरोध किया है और उन प्रोजेक्ट्स का मज़ाक भी उड़ाया है जो अब हकीकत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। समाजवादी पार्टी के नेता इस विचार का मज़ाक उड़ाते थे। आज अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वे इसके नाम से खुश नहीं हैं क्योंकि इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। हनुमानगढ़ी में नमाज़ पढ़ने की कथित घटना का ज़िक्र करते हुए, आदित्यनाथ ने सवाल किया कि ऐसी हरकत की इजाज़त क्यों दी गई और इसकी तुलना पूजा-पाठ की दूसरी जगहों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों से की। उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए—क्या कोई कभी जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? क्या कोई सरकार ऐसा करवा सकती है? क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ऐसा करवा सकती हैं? अगर वे ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर इस काम की इजाज़त क्यों दी गई? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर ऐसा क्यों किया गया? मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का श्रेय भी बीजेपी को दिया, साथ ही कांग्रेस और एसपी पर भगवान राम के अस्तित्व पर शक करने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थीं। बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। उनके ये बयान राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच आए हैं, जिसमें बीजेपी और विपक्ष अयोध्या और मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राम मंदिर विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी दलों को अयोध्या के विकास का विरोधी बताते हुए राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को दिया, जबकि विपक्षी दलों ने राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स का उपहास किया था। यह बयान राम मंदिर से जुड़े चंदे और आस्था के मुद्दों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आया है।

विवाहिता को था जान का खतरा, फोन पर मायके पक्ष से मांगी थी मदद

जौनपुर के मडियाहू इलाके में कथित तौर पर एक 24 वर्षीय विवाहिता ने अमरूद के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर जानबूझकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक, नेवढ़िया के लच्छनपूरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में शांति देवी (25) का शव अमरूद के पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ है। घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले की जानकारी विवाहिता के मायके पक्ष को भी दी गई, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मायके पक्ष का आरोप है कि शांति का शव अमरूद के पेड़ के सहारे नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ मिला था और उनके बेटी की हत्या हुई है। वहीं, ससुराल पक्ष ने आरोप लगाया है कि शांति की हत्या नहीं हुई है बल्कि उसने आत्महत्या ही की है। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर टकराव हो रहा था, इसी बीच मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि गुरुवार की रात शांति ने मायके में मोबाइल पर फोन किया था और कहा था कि उसे जान का खतरा है, यह लोग उसे मार देंगे। इसके बाद शुक्रवार की सुबह शांति का शव बरामद हुआ है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं, घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रावधान पर संवैधानिक सवाल उठाए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रावधान पर महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाए हैं। अदालत ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3-ए) की संवैधानिक वैधता की जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने संजय कुमार शर्मा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष समझने के लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि प्रेम लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2000) मामले में एक समन्वय पीठ ने इसी तरह के एक वैधानिक प्रावधान को रद्द कर दिया था। अदालत ने उस समय माना था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद '243-ई' और '243-के' के तहत पंचायतों के कार्यकाल और राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में दायर अपील का निपटारा करते हुए कानून से जुड़े सवालों को एक उचित मामले में विचार के लिए खुला छोड़ दिया था। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठता है कि क्या निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल संवैधानिक रूप से निर्धारित अवधि से आगे प्रभावी रूप से बढ़ जाता है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसी व्यवस्था पंचायत चुनाव समय पर कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है। पीठ ने इन मुद्दों के महत्व को देखते हुए निर्देश दिया कि मामले को इसी तरह के सवालों से संबंधित अन्य लंबित जनहित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

शरीयत को तवज्जो देने वालों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया करारा झटका

देश के संविधान से ज्यादा शरीयत को तवज्जो देने वाले और पंद्रह साल की उम्र की लड़की के विवाह को जायज मानने की सोच रखने वालों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करारा झटका दिया है। अदालत ने साफ और सख्त शब्दों में कहा है कि देश में विवाह की कानूनी आयु सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी और किसी भी धर्म का पसर्नल लॉ उससे ऊपर नहीं हो सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पसर्नल लॉ में यौवन प्राप्ति को विवाह की आयु मानने का प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। अदालत ने दो टूक कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े ये कानून राष्ट्रीय नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक समझ पर आधारित हैं, इसलिए इनके सामने किसी भी व्यक्तिगत कानून का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने एक जुलाई को यह महत्वपूर्ण टिप्पणी बुलंदशहर में दर्ज एक प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए की। यह याचिका रुबी समेत उन्नीस लोगों की ओर से दाखिल की गई थी। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने सोलह वर्ष की एक मुस्लिम किशोरी का विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस और बाल सहायता दल पर हमला किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली और किशोरी को जबरन वहां से ले जाने का प्रयास किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि मुस्लिम शरीयत कानून के अनुसार यौवन प्राप्त करने के बाद, जिसे सामान्य रूप से पंद्रह वर्ष की आयु माना जाता है, लड़की विवाह के लिए सक्षम हो जाती है। उनका कहना था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत विवाह कानून को प्रभावित नहीं करता। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून का ऐसा प्रावधान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम से स्पष्ट रूप से असंगत है। अदालत ने कहा कि यदि अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों का विवाह स्वीकार कर लिया जाए तो इससे बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्वाभाविक रूप से शारीरिक संबंधों से जुड़े होते हैं। ऐसे में बाल विवाह को वैध मानना बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानून को निष्प्रभावी कर देगा।